भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.03.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2293 का उत्तर

पीपीपी मॉडल पर स्टेशन

2293. श्री सुखबीर सिंह बादलः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे में पीपीपी मॉडलों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार की पीपीपी मॉडल पर ट्रैक निर्माण, ट्रैकों और रेलवे स्टेशनों के प्रबंधन की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): रेल मंत्रालय ने निजी निवेश और भागीदारी आकर्षित करने के लिए नेटवर्क विस्तार, रेल इंजन कारखानों की स्थापना, रेल मालडिब्बों की शुरूआत, स्टेशन पुनर्विकास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पहल की है।

रेल संपर्क मुहैया कराने में निजी निवेश बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा भागीदारी नीति 2012 तैयार की गई थी। इस नीति के अंतर्गत अभी तक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 6,176 करोड़ रूपए की 13 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। कोयला संपर्क और पत्तन संपर्क परियोजनाओं सहित 22,098 करोड़ रूपए की 11 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं और इसके अलावा 13,421 करोड़ रूपए की 7 अन्य परियोजनाओं को पहले ही सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव मुहैया कराने के लिए कुछ गाड़ियों में वाणिज्यिक और ऑनबोर्ड सेवाओं को आउटसोर्स करने और 'अत्याधुनिक' चल स्टॉक लगाने के उद्देश्य से

लगभग 150 आधुनिक रेक शामिल करने हेतु निजी भागीदारों को अनुमति देने का प्रस्ताव है। गाड़ी परिचालन और संरक्षा प्रमाणन की जिम्मेदारी भारतीय रेल के पास ही रहेगी।

हबीबगंज रेलवे स्टेशन के विकास का कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए शुरू किया गया है। इसके अलावा, पीपीपी माध्यम के जरिए 4 अन्य स्टेशनों यथा, नागपुर, ग्वालियर, अमृतसर और साबरमती स्टेशनों के लिए अर्हता अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित किए गए हैं।

******